वह रोजगार मिल जाने की वजह से अच्छी जिन्दगी गुजारने का मौका पाएगा ।

मैं आज फिर जौनपुर के लोगों की तरफ से जौनपुर के पिछड़ेपन और बेरोजगारी को दूर करने के लिए पुरजोर मुतालबा करता हूं कि जौनपुर में बड़ी इन्डस्ट्री लगाई जाए ताकि जौनपुर का पिछड़ापन और बेरोजगारी दूर होने में मदद मिले और जौनपुर के लोगों को राहत मिले ।

(vii) Doordarshan facilities to Shahdol district of Madhya Pradesh

श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : उपाध्यक्ष जी, शहडोल जिला एक औद्योगिक प्रधान जिला है, जो मध्यप्रदेश के लगभग मध्य बिन्दु पर स्थित है । इस जिले में 20 कोयला खदानों का जाल बिछा है, जिससे 25 हजार टन कोयले का उत्पादन प्रतिदिन होता है, जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है । इसके अतिरिक्त अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन, पेपर मिल, सोडा फैक्ट्री, पॉटरीज फैक्ट्री एवं बाक्साइड का विशाल भंडार है ।

शिक्षा की दृष्टि से यह जिला अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिसमें 7 महाविद्यालय आई० टी० आई० एवं माइनिंग पालिटेक्निक महाविद्यालय हैं, जो कि मध्यप्रदेश में एकमात्र है ।

रीवा संभाग का श्रम न्यायालय तथा सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय भी यहीं स्थित है । जनसंख्या की दृष्टि से यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है तथा यह लोकसभा, आदिवासियों के लिये सुरक्षित सीट है । बहुउद्देश्शीय बाण सागर योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन बांध इस जिले का गौरव है, जिससे मध्यप्रदेश, बिहार एवं उत्तरप्रदेश को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी ।

बिरसिंहपुर पाली में निर्माणाधीन थर्मल पावर स्टेशन भी इसी जिले में स्थित है ।

केन्द्रीय शासन ने 1984 तक भारत के 65 प्रतिशत क्षेत्र में टेलीविजन का लक्ष्य बनाया है, किन्तु शहडोल जिला इससे अछूता है, जबकि आस-पास के सभी जिलों में यह सुविधा उपलब्ध होगी ।

अतः भारत शासन से अनुरोध है कि आगामी विस्तार योजना में शहडोल जिले को सम्मिलित कर 15 अगस्त, 1984 से टेलीविजन का शुभारम्भ किया जाये ।

(viii) Termination of contract by Indian Iron and Steel Co. entered into with Damodar Cement Co. for the purchase of slag.

SHRI BASUDEB ACHARIA (Bankura) : The unilateral termination of long-term supply contract by Indian Iron and Steel Company Ltd. poses a threat to the existence of Damodar Cement, a CCI and Government of West Bengal joint enterprise, for which Industrial Development Bank of India has made 17 crore rupees loan commitment. It was in December 1980 that a deal was finalised between WBIDC and IISCO for supply of entire slag generated from latter's blast furnace at Burnpur. IISCO offered land and transportation facilities to the WBIDC for setting up of granulation plant and running it. The termination of contract may lead to the closure of Damodar Cement, resulting in heavy investment losses for CCI and West Bengal Government. The Company has already spent Rs. 2.5 crores and placed order for machinery and equipment to set up a large granulation plant at Burnpur and a cement plant in the district of Purulia. An expenditure of Rs. 6 crores has already been committed. I urge upon the Government to look into the matter.

(ix) Setting up of a Thermal Power Station at Valope or Dabhol (Ratnagiri)

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri) : Survey for establishment of a thermal power station in Ratnagiri district of Maharashtra has been completed and report was submitted to the Government a year back. It is reported that two villages—Valope in Chiplum Taluka and Dabhol in Dapoli Taluka have been extensively surveyed in this connection. No further action has yet been taken in connection with the reports submitted to the Government.

I would, therefore, request the Government to take the necessary action and take an early decision for establishing the power station either at Valope or at Dabhol and commence the construction work.

(x) Demand for better service conditions for certain categories of employees in Post Offices

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, पोस्ट आफिस के ई० डी० और सी० पी० कर्मचारियों की समस्या अत्यन्त गंभीर हो गई है। ई० डी० कर्मचारी 5 घंटे के स्थान पर आठ घंटे काम करके दो सौ रुपये से कम पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं और सी० पी० कर्मचारी अर्थात् चौकीदार 17 घटे कार्य करके 250 रुपये से भी कम प्रतिमाह प्राप्त करते हैं। सी० पी० कर्मचारियों को अवकाश भी नहीं दिया जाता तथा वे विभागीय परीक्षाओं में भी नहीं बैठने पाते। ई० डी० कर्मचारी 12-13 वर्षों तक काम करने के बाद भी नियमित नहीं किये जाते। अतः सरकार से मैं मांग करता हूं कि इन कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाय और उनकी सेवायें नियमित की जाएं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: After three years of service as an E.D. employee, any employee can sit for the Class IV examination.

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : But, Sir, here they are facing a lot of difficulty.

MR. DEPUTY-SPEAKER : All the Class IV posts are reserved for E.D. employees. I know something about this.

SHRI HARIKESH BAHADUR : Even people who have been continuously working for 12 to 13 years....

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : They have to pass an examination.

SHRI HARIKESH BAHADUR : But they have not been able to sit in the examination.

(*Interruptions*)

14.36 hrs.

RAILWAY BUDGET, 1984-85 GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : We now take up General Discussion on Railway Budget for 1984-85. Time allotted was 10 hours and time already taken was 3 hours and 4 minutes. Now the time left is 6 hours 56 minutes. Now I call Shri J.S. Patil to speak. His Party has been allotted 18 minutes and another Member from his Party also has to speak on it. This is for your information.

Now Mr. J.S. Patil may speak.

श्री जगन्नाथ पाटिल (ठाणे) : उपाध्यक्ष महोदय, कल से रेल बजट पर चर्चा हो रही है। मेरे इस ओर के साथियों ने खासकर मधु दण्डवते जी ने रेल मंत्रालय की कार्यक्षमता के बारे में बड़ी अच्छी तरह से बता दिया है। मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यापारी हमेशा नुकसान से बचने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे रेल पति जी ने 70 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है। रेलपति इसलिए कहा है कि सब लोगों की एक पत्नी होती है लेकिन रेल मंत्री महोदय वेस्टर्न रेलवे, सेंटर रेलवे, नार्दन रेलवे और ईस्टर्न रेलवे इन सबका कारोबार देखते हैं। इन्होंने 70 करोड़ रुपये के घाटे का आटा रेल के पहियों को देशभर में चलाकर दिखाया है, यह बड़ी चिंता की बात है। आज रेलगाड़ियां जिस ढंग से चलती हैं उससे मुझे पुरानी फिल्म का एक गाना याद आता है "चलती का नाम गाड़ी" उसी खटारे की तरह रेलगाड़ियां आज देशभर में चल रही हैं।

रेल बजट प्रस्तुत करते समय चुनाव वर्ष को सामने रखकर 70 करोड़ का घाटा बताया गया